दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)524/P/Fixation/Vol.VI

प्रधानकार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated:13 -07-2016

आर बी ई सं/RBE No. 73 / 2016 **पी बी सी सं/ PBC No: 85 / 2016**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units, etc.,

(As per mailing list –'A')

विषय/Sub: Fixation of pay of State Government Employees on appointment to the posts under the administrative control of Ministry of Railways.

******

A copy of Railway Board's letter No. E(P&A)II/2016/PP-1 dated 23-06-2016 (RBE No. 73 / 2016) on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter dated 02-08-2001referred therein has been circulated under PBC No. 131 / 2001.

(B.INDUMATHY)
Asst. Personnel Officer/M&E
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

संलग्न/Encl: as above

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA

The Genl Secy / NFIR

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

महाप्रबंधक का कार्यालय
GENERAL MANAGER'S OFFICE
04 JUL 2016
दक्षिण रेलवे/Southern Railway
चेन्नै/Chennai-600 003

RBE No. 73/2016.

No. E(P&A)II/2016/PP-1. **New Delhi, dated 23 .06.2016.**

The General Managers,
All Indian Railways
& Production Units etc.

Sub. : Fixation of pay of State Government Employees on appointment to the posts under the administrative control of Ministry of Railways.

*****

The method of fixation of pay of State Government servants on appointment to posts under the administrative control of Ministry of Railways has been spelt out in Board's letter No. E(P&A)-II-2001/PP-7 dated 02-08-2001. The question of fixation of pay in such cases consequent upon revision of pay scales on acceptance of the recommendations of the VIth Central Pay Commission in the revised pay structure has been considered by the Government and the President is pleased to decide that in the cases of State Government employees appointed to post under the administrative control of the Ministry of Railways on or after 01/01/2006, pay will be fixed in the following manner :-

(a) Where the State Government has revised the Pay scales of their employees on the pattern of VIth Central Pay Commission at the **base index of 115.76 as per AICPI(IW) 2001 series** w.e.f 1.1.2006, the pay of these State Government employees on their appointment to the posts under the administrative control of Ministry of Railways would be fixed as follows :

(i) When the appointment is to a post carrying higher Grade Pay, one increment equal to 3% of the sum of the pay in the existing grade pay will be computed and rounded off to the next multiple of 10. This will then be added to the existing pay in the pay band. The grade pay corresponding to the higher post will thereafter be granted in addition to this pay in the pay band. In cases where the appointment involves change in pay band also, the same methodology will be followed. However, if the pay in the pay band after adding the increment is less than the minimum of the higher pay band to which the appointment is taking place, pay in the pay band will be stepped up to such minimum.

(ii) Where the appointment is to a post involving identical Grade Pay, the individual shall continue to draw the same pay.

(b) Where the State Government have revised the pay scales of their employees after 1.1.2006 **beyond the base index of 115.76 as per AICPI(IW) 2001 series,** basic pay of the employees is to be determined first in the Scale applicable on Railways by reducing the element of DA, ADA, IR etc. granted by the State Government after 1.1.2006 (**beyond the base index of 115.76 as per AICPI (IW) 2001 series**) and thereafter the pay would be fixed as provided in the clause (i) & (ii) under sub-para (a) above.

(c) Where the State Government have either not revised or revised the pay scale of their employees on or after 1.1.2006 below **the base index of 115.76 as per AICPI(IW) 2001 series,** basic pay of these employees shall be determined first in

the scale applicable on Railways, by adding the element of DA, ADA upto **base index of 115.76 as per AICPI(IW) 2001 series,** granted by the State Government and thereafter their pay would be fixed as provided in the clause (i) & (ii) under sub-para (a) above.

2. These orders are applicable to employees of the State Government and local bodies under the State including Emergency Divisional Accountants/Divisional Accountants/local bodies under the State Government appointed to a post under the administrative control of the Ministry of Railways on or after 1.1.2006.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Md. Salim Ahmed.

(Salim Md. Ahmed)
Dy. Director, Estt. (P&A)II
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

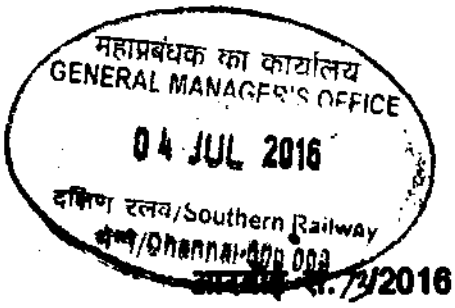

सं. ई(पी एण्ड ए)-II/2016/पीपी-1

नई दिल्ली, दिनांक 29/06/2016

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय- रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले पदों पर राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति होने पर उनके वेतन का निर्धारण करना।

*****

रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले पदों पर नियुक्ति होने पर राज्य सरकार के सेवकों का वेतन निर्धारित करने की विधि बोर्ड के दिनांक 02.08.2001 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)-II-2001/पीपी-7 में दी गयी है। संशोधित वेतन संरचना में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने पर वेतनमानों में संशोधन करने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा ऐसे मामलों में वेतन निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है और राष्ट्रपति जी ने यह सहर्ष निर्णय लिया है कि 01/01/2006 को या उसके बाद रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामलों में वेतन का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:-

(क) जहां राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतनमान छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर 1.1.2006 से लागू एआईसीपीआई(आईडब्ल्यू) 2001 सिरीज के अनुसार 115.76 के आधार सूचकांक पर संशोधित किया है, ऐसे मामलों में रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले पदों पर नियुक्ति होने पर राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतनमान निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

(i) यदि नियुक्ति उच्चतर ग्रेड पे वाले किसी पद पर हो, तो मौजूदा ग्रेड पे में वेतन की राशि के 3% के बराबर एक वेतनवृद्धि आकलित की जाएगी और उसे अगले 10 के गुणांक में पूर्णांकित किया जाएगा। उसके बाद, उसे पे बैण्ड में मौजूदा वेतन में जोड़ा जाएगा। उसके बाद उस पे बैण्ड में इस वेतन के अलावा उच्चतर पद के अनुरूप ग्रेड पे प्रदान किया जाएगा। यदि नियुक्ति में पे बैण्ड में भी परिवर्तन हो तो यही विधि अपनाई जाएगी। बहरहाल, यदि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी पे बैण्ड में वेतन उस उच्चतर पे बैण्ड, जिसमें नियुक्ति हो रही हो, के न्यूनतम वेतन से कम हो, तो उस पे बैण्ड में वेतन को बढ़ाकर न्यूनतम वेतन के बराबर कर दिया जाएगा।

(ii) जहां नियुक्ति समान ग्रेड पे वाले किसी पद पर हो, तो कर्मचारी वही वेतन प्राप्त करता रहेगा।

(ख) यदि राज्य सरकार ने 1.1.2006 के बाद अपने कर्मचारियों के वेतनमानों में एआईसीपीआई(आईडब्ल्यू) 2001 सिरीज के अनुसार 115.76 के आधार सूचकांक के बाहर संशोधित किया हो, तो कर्मचारियों का मूल वेतन सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा 1.1.2006 के बाद एआईसीपीआई(आईडब्ल्यू) 2001 सिरीज के अनुसार 115.76 के आधार सूचकांक से बाहर) प्रदान किए गए डीए, एडीए, आईआर का तत्व घटाकर रेलों में लागू वेतनमान में निर्धारित किया जाएगा और उसके बाद उपर्युक्त उप-पैरा (क) के अंतर्गत खण्ड (i) और (ii) में दिए गए अनुसार वेतन निर्धारित किया जाएगा।

(ग) यदि राज्य सरकार ने 1.1.2006 को या उसके बाद या तो अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन नहीं किया हो या वेतनमान में संशोधन एआईसीपीआई (आईडब्ल्यू) 2001 सिरीज के अनुसार 115.76 के आधार सूचकांक से नीचे निर्धारित किया हो, तो कर्मचारियों का मूल वेतन सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए एआईसीपीआई(आईडब्ल्यू) 2001 सिरीज के अनुसार 115.76 के आधार सूचकांक तक डीए, एडीए का तत्व जोड़कर रेलों में लागू वेतनमान में निर्धारित किया जाएगा और उसके बाद उनका वेतन उपर्युक्त उप-पैरा (क) के अंतर्गत खण्ड (i) और (ii) में दिए गए अनुसार निर्धारत किया जाएगा।

2. ये आदेश रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत किसी पद पर 1.1.2006 को या उसके बाद नियुक्त आपातकालीन मंडल लेखाकारों/मंडल लेखाकारों/राज्य सरकार के अन्तर्गत स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है

मो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)
उप निदेशक, स्था.(पी एण्ड ए),
रेलवे बोर्ड